IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

WRIT PETITION NO. 1105 (MS) OF 2001

Old No. 21039/1989

State of U.P. .....Petitioner.

Versus

1. Narendra Kumar,
   S/o Sultan Singh,
   Village Jasowala Pargana Western,
   Dehradun District-Dehradun.
2. Rehabilitation Centre Head Quarter,
   Establishment No. 22 C/o 56 A.P.O.
3. Tibbatian Sayunkt Sahkari Krishi Samiti Ltd. Lakhanwala, Newat pargana Pachhwadoon Post Office Harbartpur, District Dehradun. .....Respondents.

Dated: 08.06.2006

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

Heard Standing Counsel for the State, Sri Arvind Vashisth and Sri Lok Pal Singh, Advocate for the respondents.

By the present writ petition, the petitioner has prayed for a writ of certiorari quashing the order dated 01.06.1989 passed by the Commissioner (Annexure No. 4 to the writ petition).

Briefly stated, during the proceedings under U.P. Imposiiton of Ceiling of land Holdings Act were initiated, the Prescribed Authority has declared the land as surplus. The respondent went in appeal. The appellate Court has recorded a finding that the land in question, which has been declared

surplus was exempted from the ceiling proceeding. The relevant findings to that effect are quoted below:-

"प्रारम्भ में ही यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि यह अपील स्वीकार होने योग्य है। विचारणीय है कि विवादित भूमि सीलिंग से अवमुक्त थी और उसकी बिक्री तभी हो गई थी जब ऐसी अवमुक्त भूमि के अन्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। यही नहीं 22 इस्टाब्लिप्रामेन्ट एवं उ0प्र0 सरकार के नाम पर अन्तरण के आधार पर दाखिल खारिज भी हो चुका है तथा दो बार पूर्व में बिक्री हुई भूमि को अपीलार्थी के खाते से हुआ है जब कि सीलिंग से अवमुक्त भूमि के अन्तरण पर संप्रोधन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया।

बिक्री हुई भूमि किसी व्यक्ति विप्रोष के नाम पर अन्तरिम न हो कर उ0प्र0 सरकार एवं प्रासन के एक संस्थान 22 इस्टाब्लिप्रामेन्ट के नाम पर हुई है। यदि बिक्री हुई भूमि अतिरिक्त घोषित हो सकती है तो ऐसी भूमि को क्रय करने का उत्तरदायित्व स्वयं शासन पर आता है। अतः अपने उत्तरदायित्व के लिये शासन अपीलार्थी के खाते से भूमि नही मांग सकता और यदि वास्तव में शासन बिक्री हुई भूमि को अतिरिक्त घोषित भूमि पहले ही अपीलार्थी के खाते से बाहर निकल चुकी है अतः उसके एवज में कोई अन्य भूमि मांगना उपयुक्त नहीं है।:

In view of the findings that the surplus land having already been taken out form the land of the respondents and therefore, the appeal has rightly been allowed. I do not find any infirmity in the order so as to interfere under Article 226/227 of the Constitution of India.

The writ petition lacks merit and is dismissed. No order as to costs.

(Rajesh Tandon, J.)

08.06.2006

Rathour